



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 2017/फाल्गुन 25, 1938

No. 198]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 2017/PHALGUNA 25, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2017

सा. का. नि. 254(अ).—बंदी सम्प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध 28 मई, 2016 से मंगोलिया पर लागू होंगे तथा उस देश तथा भारत के बीच बंदियों के अंतरण के प्रयोजन से दिनांक 17.05.2015 को हस्ताक्षरित दंडित व्यक्तियों के अंतरण के बारे में भारत गणराज्य की सरकार एवं मंगोलिया की सरकार के बीच हुई संधि तथा 28.04.2016 को आदान-प्रदान किए गए अनुसमर्थन के दस्तावेजों के संपूर्ण पाठ को निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

“दंडित व्यक्तियों के अंतरण के संबंध में

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

मंगोलिया सरकार

के बीच

संधि

भारत गणराज्य तथा मंगोलिया सरकार (जिन्हें इसमें इसके बाद “संविदाकार देश” कहा गया है)

सम्प्रभुता, समानता और पारस्परिक लाभ के लिए परस्पर सम्मान के आधार पर

दंडित व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुकर बनाने के लिए उन्हें अपनी सजा अपनी राष्ट्रीयता वाले देश में काटने के उद्देश्य से निम्न प्रकार सहमत हो गई हैं:

अनुच्छेद 1

परिभाषाएं

इस संधि के प्रयोजनार्थ:

(क): “अंतरणकर्ता देश” से वह देश अभिप्रेत है जो दंडित व्यक्ति को अपने भू-भाग से अंतरित करे अथवा जिसने उसे अंतरित किया हो;

- (ख): “प्राप्तकर्ता देश” से वह उस देश अभिप्रेत है जो दंडित व्यक्ति को अपने भू-भाग में लेता है अथवा लिया हो;
- (ग): “दंडित व्यक्ति” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अंतरणकर्ता देश में किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दण्ड दिया गया हो;
- (घ): “निर्णय” से दण्ड देने वाले किसी न्यायालय अथवा अधिकरण का कोई निर्णय अथवा आदेश अभिप्रेत है;
- (ङ.): “दण्ड” से कोई ऐसा दंड अथवा उपाय अभिप्रेत है जिसमें किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा अपने दांडिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उसके द्वारा आदेशित स्वतंत्रता का वचन अथवा आजीवन कारावास शामिल हो;

## अनुच्छेद 2 सामान्य सिद्धांत

इस संधि के प्रावधानों के अनुसार और अपने देश के कानून के अधीन प्रत्येक देश किसी दंडित व्यक्ति को दूसरे देश में अंतरित कर सकता है ताकि अंतरणकर्ता देश के न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को प्राप्तकर्ता देश के भू-भाग में प्रवृत्त किया जा सके। इस संबंध में, दंडित व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जो उसकी ओर से कार्रवाई करने का हकदार है, इस संधि के अंतर्गत अंतरित किए जाने हेतु दंडित व्यक्ति की इच्छा व्यक्त कर सकता है।

## अनुच्छेद 3 केन्द्रीय प्राधिकारी

1. इस संधि को लागू करने के प्रयोजन से ये देश इसके लिए अभिहित केन्द्रीय प्राधिकारियों के माध्यम से एक दूसरे देश को सूचित करेंगे।
2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित प्राधिकारी भारत गणराज्य की ओर से गृह मंत्रालय तथा मंगोलिया की ओर से न्याय मंत्रालय होंगे।
3. यदि इनमें से कोई देश अपने अभिहित केन्द्रीय प्राधिकारी को बदलता है तो वह परिवर्तन के बारे में राजनयिक चैनलों के माध्यम से दूसरे देश को लिखित में अधिसूचित करेगा।

## अनुच्छेद 4 अंतरण की शर्तें

1. इस करार के अंतर्गत किसी दंडित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर अंतरित किया जा सकता है:
  - (क) दंडित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक हो;
  - (ख) दंडित व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया गया हो;
  - (ग) दंडित व्यक्ति को जिस आचरण के लिए दंड दिया गया था, वह प्राप्तकर्ता देश के कानून के अंतर्गत भी एक दांडिक अपराध हो;
  - (घ) अंतरणकर्ता देश, जिसमें दंडित व्यक्ति की उपस्थिति अपेक्षित है, में दंडित व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही लंबित नहीं हो;
  - (ङ) दंडित व्यक्ति पर अधिरोपित निर्णय आगे और अपीलों की संभावना के बिना प्रभावी हो;
  - (च) अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय, दंडित व्यक्ति द्वारा भोगी जाने वाली सजा की अवधि कम से कम एक वर्ष बची हो।
  - (छ) अंतरण के संबंध में सहमति लिखित में दंडित व्यक्ति द्वारा अथवा किसी भी देश द्वारा उस व्यक्ति की आयु, शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर, जरूरी समझे जाने पर उस व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा दी गई हो;
  - (ज) दोनों देश अंतरण के संबंध में सहमत हों; और

(झ) प्राप्तकर्ता देश में दंडित व्यक्ति की अभिरक्षा का अंतरण अंतरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा अन्य किसी हित के लिए हानिकर नहीं होगा।

2. आपवादिक मामलों में, ये देश ऐसी स्थिति में भी अंतरण के लिए सहमत हो सकते हैं जब भले ही दंडित व्यक्ति द्वारा भोगी जाने वाली सजा की बची अवधि इस अनुच्छेद के पैरा 1 (च) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि से कम हो।

### **अनुच्छेद 5** **अपेक्षित दस्तावेज**

(1) यदि अंतरण का अनुरोध किया गया है तो अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज अथवा विवरण प्रदान करेगा जब तक कि उस देश, जिससे अनुरोध किया गया है, ने पहले ही यह उल्लेख न कर दिया हो कि वह अंतरण पर सहमत नहीं होगा:

- (क) निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा विधि के संगत प्रावधान जिन पर निर्णय आधारित है;
  - (ख) दंड का स्वरूप, अवधि और उसके आरंभ की तारीख;
  - (ग) दंड की सजा काटने के दौरान व्यक्ति के व्यवहार तथा पहले से काटी गई सजा की अवधि तथा काटी जाने वाली सजा की शेष अवधि और विचारण-पूर्व कैद में बिताए गए समय, दंड में किसी कमी और दंड के प्रवर्तन से संबंधित अन्य कारकों के बारे में एक विवरण;
  - (घ) इस संधि के अनुच्छेद 4 के पैरा 1 (ड.) में यथा उल्लिखित अंतरण के बारे में सहमति की एक लिखित घोषणा; और
  - (ङ) दंडित व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करेगा:
- (क) यह स्पष्ट करने संबंधी दस्तावेज अथवा विवरण कि दंडित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का राष्ट्रिक है;
  - (ख) प्राप्तकर्ता देश के कानून के संगत उपबंध जिनमें यह निर्धारित किया गया हो कि दंडित व्यक्ति को जिस आचरण के लिए दंड दिया गया था वह दंडित अपराध भी है; और
  - (ग) अंतरणकर्ता देश द्वारा दिए गए दंड के प्रवर्तन के लिए प्राप्तकर्ता देश के अपने कानून के अंतर्गत इसकी प्रक्रियाओं के बारे में सूचना।

### **अनुच्छेद 6** **अनुरोध और उत्तर**

1. कोई दंडित व्यक्ति इस संधि के अंतर्गत अंतरण के लिए किसी भी देश को आवेदन कर सकता है। जिस देश को दंडित व्यक्ति ने अंतरण के लिए आवेदन किया हो, उसे आवेदन के बारे में लिखित में दूसरे देश को अधिसूचित करना चाहिए।
2. अंतरण के लिए अनुरोध किसी भी देश द्वारा किया जा सकता है। जिस देश से अनुरोध किया गया है, वह इस निर्णय के बारे में अनुरोधकर्ता देश को तत्काल यह सूचित करेगा कि वह अंतरण के लिए किए गए अनुरोध से सहमत है अथवा नहीं।
3. अंतरण के लिए अनुरोध तथा उससे संबंधित उत्तर लिखित में दिए जाएंगे और वे इस संधि के अनुच्छेद 3 के पैरा 1 में यथा उपबंधित चैनलों के माध्यम से भेजे जाएंगे।

### **अनुच्छेद 7** **दंडित व्यक्तियों को अधिसूचना**

1. प्रत्येक देश, अपने भू-भाग में, दंडित व्यक्तियों, जिनके लिए यह संधि लागू है, को यह अधिसूचित करेगा कि उनको इस संधि के उपबंधों के अनुसार अंतरित किया जा सकता है।

2. प्रत्येक देश अपने भू-भाग में संबंधित दंडित व्यक्तियों को, इस संधि के अनुच्छेद 5 और 6 के अनुसार अंतरण के अनुरोध प्राप्त होने पर अंतरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश द्वारा किए जाने वाले उपायों अथवा किए गए निर्णयों के बारे में, लिखित में सूचित करेगा।

### **अनुच्छेद 8** **दंडित व्यक्ति की सहमति और इसका सत्यापन**

1. अंतरणकर्ता देश, अपने कानून अथवा उसकी प्रक्रियाओं के अनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि दंडित व्यक्ति अथवा उसका विधिक प्रतिनिधि अंतरण के विधिक परिणामों की पूरी जानकारी के साथ अंतरण के बारे में स्वेच्छा से सहमति देगा और अंतरण की सहमति का उल्लेख करते हुए एक घोषणा में इस प्रकार की जानकारी की पुष्टि करेगा।

2. जहां प्राप्तकर्ता देश अनुरोध करे, तो अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को एक अभिहित अधिकारी के माध्यम से यह सत्यापित करने का अवसर प्रदान करेगा कि दंडित व्यक्ति ने उक्त पैराग्राफ में निर्धारित शर्तों के अनुसार सहमति व्यक्त की है।

### **अनुच्छेद 9** **अंतरित व्यक्ति को सौंपा जाना**

जब किसी अंतरण के बारे में करार हो जाए, तो देश इस संधि के अनुच्छेद 3 के पैरा 1 में यथा उपबंधित चैनलों के माध्यम से परामर्श के द्वारा अंतरण का समय, स्थान और प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे।

### **अनुच्छेद 10** **दंड का सतत प्रवर्तन**

1. दंडित व्यक्ति को लेने के बाद, प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश द्वारा निर्धारित दंड की प्रकृति और अवधि के अनुसरण में दंड के प्रवर्तन को जारी रखेगा।

2. यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा यथा निर्धारित दंड अपनी प्रकृति अथवा अवधि की दृष्टि से प्राप्तकर्ता देश के अपने कानून से असंगत है तो प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश की पूर्व सहमति से इसी प्रकार के अपराध के लिए अपने देश के कानून द्वारा निर्धारित दंड के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। जब दंड में परिवर्तन किया जाए तो:

(क) प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश द्वारा दिए गए निर्णय से प्रतीत होने वाले तथ्यों के निष्कर्षों से आवद्ध होगा;

(ख) प्राप्तकर्ता देश कारावास के दंड को आर्थिक दंड में परिवर्तित नहीं करेगा;

(ग) परिवर्तित दंड, प्रकृति जहां तक संभव हो, अंतरणकर्ता देश के न्यायालयों द्वारा अधिरोपित दंड के अनुरूप होगा।

(घ) परिवर्तित दंड, प्रकृति अथवा अवधि की दृष्टि से अंतरणकर्ता देश द्वारा अधिरोपित दंड से और कड़ा नहीं होगा और न ही प्राप्तकर्ता देश के कानून द्वारा निर्धारित इसी प्रकार के दंडिक अपराध के लिए लागू सजा की अधिकतम अवधि से अधिक होगा;

(ङ) अंतरणकर्ता देश के भू-भाग में कारावास के दंड के अंतर्गत दंडित व्यक्ति द्वारा पहले से भोगी गई सजा की अवधि को कम कर दिया जाएगा।

3. अंतरण के पश्चात् दंड का सतत प्रवर्तन, दंड में कमी तथा पैरोल के लिए निर्धारित कानूनों तथा प्रक्रियाओं और दंड के प्रवर्तन के दौरान अपनाए जाने वाले अन्य उपायों को शासित करने संबंधी कानूनों तथा प्रक्रियाओं सहित प्राप्तकर्ता देश के कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा।

### अनुच्छेद 11

#### अंतरणकर्ता देश के लिए दंड के समापन का प्रभाव

जब प्राप्तकर्ता देश इस करार के अनुच्छेद 13 के पैरा 1 (क) के अंतर्गत अंतरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि सजा पूरी हो गई है तो यह अधिसूचना अंतरणकर्ता देश में उस सजा को समाप्त करने में प्रभावी मानी जाएगी।

### अनुच्छेद 12

#### निर्णय की समीक्षा, माफी, राजक्षमा अथवा लघुकरण

1. केवल अंतरणकर्ता देश ही निर्णय की समीक्षा से संबंधित किसी आवेदन पत्र पर निर्णय करेगा।
2. कोई भी संविदाकार देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुसार दंड की माफी, राजक्षमा प्रदान कर सकेगा अथवा दंड को कम कर सकेगा।

### अनुच्छेद 13

#### दंड के प्रवर्तन के बारे में सूचना

प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन से संबंधित अंतरणकर्ता देश को ऐसी स्थिति में सूचित करेगा, जब:

- (क) दंड का प्रवर्तन पूरा हो गया हो;
- (ख) दंड का प्रवर्तन पूरा होने से पूर्व दंडित व्यक्ति हिरासत से भाग गया हो अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो; अथवा
- (ग) अंतरणकर्ता देश किसी विशिष्ट विवरण का अनुरोध करे।

### अनुच्छेद 14

#### ट्रांजिट

1. जब एक देश को किसी अन्य देश के भू-भाग से होकर दंडित व्यक्तियों के अंतरण के बारे में किसी तीसरे देश के साथ किसी करार को लागू करना हो तो पहला देश इस प्रकार के ट्रांजिट के लिए उस देश से अनुमति प्राप्त करेगा।
2. जहां हवाई परिवह का प्रयोग किया जाना हो और दूसरे देश के भू-भाग में कोई लैण्डिंग नहीं करनी हो तो इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।
3. जिस देश से अनुरोध किया गया है, वह देश, जहां तक यह उसके देश के कानून के विपरीत न हो, अनुरोधकर्ता देश द्वारा अंतरण के लिए किए गए अनुरोध को स्वीकार करेगा।

### अनुच्छेद 15 भाषाएं

इस संधि के प्रयोजन के लिए देशों के केन्द्रीय प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ अंग्रेजी में सम्प्रेषण कर सकते हैं। तथापि, सहायक सामग्री एक देश की राजभाषा में प्रदान की जाएगी तथा इसका दूसरे देश की राजभाषा में अनुवाद किया जाएगा।

### अनुच्छेद 16 वैधीकरण से छूट

इस संधि के प्रयोजन के लिए देशों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तैयार किए गए तथा इस संधि के अनुच्छेद 3 के पैरा 1 में उपबंधित चैनलों के माध्यम से प्रेषित किसी दस्तावेज, जिस पर एक देश के सक्षम प्राधिकारियों के हस्ताक्षर अथवा मोहर हो, का किसी भी तरह के वैधीकरण के बिना दूसरे देश के भू-भाग में प्रयोग किया जा सकता है।

### अनुच्छेद 17 लागत

1. प्राप्तकर्ता देश निम्नलिखित से संबंधित लागतों को वहन करेगा:  
(क) दंडित व्यक्ति के अंतरण पर आने वाली लागत, अंतरणकर्ता देश के भू-भाग में अनन्य रूप से वहन की गई लागतों के सिवाय  
(ख) अंतरण के पश्चात दंड का सतत प्रवर्तन पर आने वाली लागत।
2. प्राप्तकर्ता देश को सभी अथवा आंशिक लागतों की वसूली दंडित व्यक्ति से करने का अधिकार है।

### अनुच्छेद 18 विवादों का निपटान

इस संधि की व्याख्या, इसके लागू होने अथवा कार्यान्वयन से संबंधित किसी विवाद के संबंध में केन्द्रीय प्राधिकारी स्वयं किसी समझौते पर पहुंचने में असमर्थ हों तो इसका समाधान राजनयिक चैनलों के माध्यम से किया जाएगा।

### अनुच्छेद 19 प्रवर्तन तथा समापन

1. यह संधि अनुसमर्थन के अधीन है। अनुसमर्थन की लिखतों का आदान-प्रदान नई दिल्ली में किया जाएगा। यह अनुसमर्थन की लिखत के आदान-प्रदान की तारीख के बाद तेरहवें दिन प्रवृत्त होगी।
2. कोई भी देश राजनयिक चैनलों के माध्यम से दूसरे देश को लिखित में सूचना देकर इस संधि को किसी भी समय समाप्त कर सकता है। समापन, सूचना देने की तारीख के बाद एक सौ अठारहवें दिन प्रभावी होगा।
3. यह संधि इसके प्रवर्तन के पश्चात किए गए अंतरण के किसी अनुरोध के लिए लागू होगी भले ही संगत दांडिक अपराध इस संधि के प्रवर्तन से पहले किया गया हो।

इस संधि के साक्षी के रूप में अपनी-अपनी सरकारों की ओर से उचित रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसे 17 मई, 2015 को उलानबाटार में हिंदी, मंगोलियन और अंग्रेजी भाषाओं में तैयार किया गया है तथा इसके सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं। व्याख्या में किसी अंतर की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

ह./-

(सोमनाथ घोष)

मंगोलिया में भारत के

असाधारण एवं पूर्णाधिकारी दूत

मंगोलिया सरकार की ओर से

ह./-

(डी. डोरलिगजव)

मंगोलिया के न्याय मंत्री

[फा. सं. V-17011/04/2015-पी आर]

दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2017

**G.S.R.254(E).**— In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 3 of Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to Mongolia with effect from the 28<sup>th</sup> day of May, 2016, and notifies the full text of the treaty entered into between the Government of the Republic of India and the Government of the Mongolia on 17.5.2015 and Instruments of Ratification exchanged on 28.4.2016 for the transfer of prisoners between that country and India as follows, namely :-

### TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

The Government of the Republic of India and the Government of Mongolia (hereinafter referred to as “the Contracting States”)

On the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit.

In order to have sentenced persons to serve their sentences in their country of nationality to facilitate their social rehabilitation.

Have agreed as follows:

#### ARTICLE 1 DEFINITIONS

For the purpose of this Treaty:

- (a) “Transferring State” means the State which may transfer or has transferred a sentenced person out of its territory;
- (b) “Receiving State” means the State which may receive or has received a sentenced person into its territory;

- (c) “Sentenced person” means a person who has been sentenced to imprisonment by a court in the Transferring State;
- (d) “Judgment” means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (e) “Sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time or for life imprisonment in the exercise of its criminal jurisdiction;

## **ARTICLE 2 GENERAL PRINCIPLES**

Each State may, in accordance with the provisions of this Treaty and subject to its domestic law, transfer a sentenced person to the other State to enforce the sentence imposed on the person by the court of the Transferring State in the territory of the Receiving State. To that end, the sentenced person or any other person who is entitled to act on the sentenced person’s behalf may express the sentenced person’s willingness to be transferred under this Treaty.

## **ARTICLE 3 CENTRAL AUTHORITIES**

1. For the purpose of implementing this Treaty, the States shall communicate with each other through the Central Authorities designated therefore.
2. The Central Authorities referred to in Paragraph 1 of this Article shall be the Ministry of Home Affairs for the Republic of India and the Ministry of Justice for Mongolia.
3. Should either State change its designated Central Authority, it shall notify the other State of such a change in writing through diplomatic channels.

## **ARTICLE 4 CONDITIONS FOR TRANSFER**

1. A sentenced person may be transferred under this Agreement on the following conditions:
  - (a) the sentenced person is a national of the Receiving State;
  - (b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
  - (c) the conduct on account of which the sentence was imposed on the sentenced person also constitutes a criminal offence under the laws of the Receiving State;
  - (d) no criminal proceeding is pending against the sentenced person in the transferring State in which his presence is required.
  - (e) the judgment imposed on the sentenced person is effective without any possibility of further appeals;
  - (f) at the time of the receipt of request for transfer, the sentenced person still has at least one year left of the sentence to serve;
  - (g) the transfer is consented to in writing by the sentenced person, or by the person’s legal representative when either State considers it necessary in view of the person’s age, physical or mental condition;



(h) both States agree to the transfer; and

(i) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other interest of the transferring State

2. In exceptional cases, the States may agree to a transfer even if the period of time left to be served by the sentenced person is less than that as specified in Paragraph 1(f) of this Article.

## **ARTICLE 5 REQUIRED DOCUMENTS**

1. If a transfer is requested, the transferring State shall provide the following documents or statements to the Receiving State, unless the requested State has already indicated that it will not agree to the transfer:

- (a) a certified copy of the judgment, including the relevant provisions of law on which the judgment is based;
- (b) a statement indicating the nature, duration and date of commencement of Sentence;
- (c) a statement describing the behavior of the person during the service of the sentence and the period of time already served and remaining to be served as well as time spent in pre-trial detention, any reduction of sentence and other factors relevant to enforcement of the sentence;
- (d) a written declaration of the consent to the transfer as referred to in Paragraph 1(e) of Article 4 of this Treaty; and
- (e) a statement indicating the physical and mental conditions of the sentenced person.

(2) The Receiving State shall provide the Transferring State with the following documents:

- (a) documents or statements certifying that the sentenced person is a national of the Receiving State;
- (b) relevant provisions of the law of the Receiving State stipulating that the conduct for which the sentence was imposed on the sentenced person also constitutes a criminal offence; and
- (c) information on the procedures of Receiving State, under its domestic law, to enforce the sentence imposed by the Transferring State.

## **ARTICLE 6 REQUESTS AND REPLIES**

- 1. A sentenced person may apply to either State for transfer under this Treaty. The State to which the sentenced person has made an application for transfer must notify the other State in writing of the application.
- 2. A request for transfer may be made by either State. The requested State shall promptly inform the requesting State of its decision as to whether or not to agree to the requested transfer.
- 3. Requests for and replies to transfers shall be made in writing and transmitted through the channels as provided for in Paragraph 1 of Article 3 of this Treaty.

## **ARTICLE 7 NOTIFICATION TO THE SENTENCED PERSONS**

- 1. Each State shall, within its territory, notify the sentenced persons, to whom this Treaty is applicable, that they may be transferred in accordance with provisions of this Treaty.

2. Each State shall inform in writing the sentenced persons concerned within its territory of the measures taken or decisions made by the Transferring State or the Receiving State upon requests for transfer in accordance with Articles 5 and 6 of this Treaty.

#### **ARTICLE 8**

#### **CONSENT OF THE SENTENCED PERSON AND ITS VERIFICATION**

1. The Transferring State shall in accordance with its law or the procedures 'thereof ensure that the sentenced person or his or her legal representative voluntarily gives consent to the transfer with full knowledge of the legal consequences of the transfer and confirms such knowledge in a declaration indicating consent to the transfer.
2. Where the Receiving State requests, the Transferring State shall afford the opportunity to the Receiving State to verify, through a designated official, that the sentenced person has expressed consent in accordance with the conditions set out in the paragraph above.

#### **ARTICLE 9**

#### **DELIVERY OF THE TRANSFERRED PERSON**

Where an agreement is reached on a transfer, States shall determine the time, place and procedure for transfer, by means of consultation through the channels as provided for in Paragraph 1 of the Article 3 of the this Treaty.

#### **ARTICLE 10**

#### **CONTINUED ENFORCEMENT OF THE SENTENCE**

1. After receiving the sentenced person, the Receiving State shall continue to enforce the sentence pursuant to the nature and duration of the sentence determined by the Transferring State.
2. If, the sentence as determined by the Transferring State is by its nature or duration incompatible with the domestic law of Receiving State, the Receiving State may, with the prior consent of Transferring State, adapt the sentence to a sentence prescribed in accordance with the sentence prescribed by its own domestic law for a similar offence. When adapting the sentence:
  - (a) the Receiving State shall be bound by the findings of facts insofar as they appear from the judgment imposed by the Transferring State;
  - (b) the Receiving State shall not adapt a penalty of imprisonment to a pecuniary penalty;
  - (c) the adapted sentence shall, as far as possible, correspond with the sentence imposed by the courts of the Transferring State.
  - (d) the adapted sentence shall be no more severe than that imposed by the Transferring State in terms of the nature or duration, nor exceed the maximum duration of penalty applicable to a similar criminal offence prescribed by the law of the Receiving State;
  - (e) the period of time already served by the sentenced person under a sentence of imprisonment in the territory of the Transferring State shall be deducted.
3. The continued enforcement of the sentence after the transfer shall be governed by the laws and procedures of the Receiving State, including those providing for the reduction of sentence and parole and those governing other measures adopted during the enforcement of sentence.

#### **ARTICLE 11**

#### **EFFECT OF COMPLETION OF SENTENCE FOR THE TRANSFERRING STATE**

When the receiving State notifies the transferring State under paragraph 1(a) of Article 13 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging that sentence in the transferring State.

**ARTICLE 12**  
**REVIEW OF JUDGMENT AND PARDON, AMNESTY OR COMMUTATION**

1. The transferring State alone shall decide on any application for the review of the judgment.
2. Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.

**ARTICLE 13**  
**INFORMATION ON THE ENFORCEMENT OF THE SENTENCE**

The Receiving State shall provide information to the Transferring State concerning the enforcement of the sentence when:

- (a) the enforcement of the sentence has been completed
- (b) the sentenced person has escaped from custody or died before the enforcement of the penalty has been completed; or
- (c) the Transferring State requests a specific statement.

**ARTICLE 14**  
**TRANSIT**

1. When one State is to implement an agreement with a third country on the transfer of sentenced persons through the territory of the other State, the former State shall request permission from the State for such a transit.
2. Such permissions are not required where air transportation is used and no landing in the territory of the other State is Scheduled.
3. The requested State shall, insofar as it is not contrary to its domestic law, grant the request for transit made by the requesting State.

**ARTICLE 15**  
**LANGUAGES**

For the purpose of this Treaty, the Central Authorities of the States may communicate with each other in English. However, supporting materials shall be provided in the official language of one State, and translated into the official language of the other State.

**ARTICLE 16**  
**EXEMPTION FROM LEGALIZATION**

For the purpose of this Treaty, any document made by competent authorities of the States and transmitted through the channels provided for in paragraph 1 of Article 3 of this Treaty, affixed with the signature or seal of the competent authorities of one State, may be used in the territory of the Other State without any form of legalization.

**ARTICLE 17**  
**COSTS**

- 1 The Receiving State shall bear the costs of:
  - (a) the transfer of the sentenced person, except the costs incurred exclusively in the territory of the Transferring State; and
  - (b) the continued enforcement of the sentence after the transfer.
2. The Receiving State has the right to recover all or part of the costs from the sentenced person.

**ARTICLE 18**  
**SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute arising out of the interpretation, application, or implementation of this Treaty shall be resolved through diplomatic channels if the Central Authorities are themselves unable to reach an agreement.

**ARTICLE 19**  
**ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION**

1. This Treaty is subject to ratification. The instruments of ratification shall be exchanged at New Delhi. This shall enter into force on the thirtieth day after the date of the exchange of the instruments of ratification.

2. Either State may terminate this Treaty at any time by notice in writing to the other State through diplomatic channels. Termination shall take effect on the one hundred and eightieth day after the date on which the notification is given.

3. This Treaty applies to any requests for transfer presented after its entry into force even if the relevant criminal offences before the entry into force of this Treaty.

**In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.**

Done in duplicate at Ulaanbaatar on this 17<sup>th</sup> day of May 2015, in Hindi, Mongolian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

**ON BEHALF OF THE GOVERNMENT  
OF THE REPUBLIC OF INDIA**

Sd/-  
( SOMNATH GHOSE )  
AMBASSADOR EXTRAORDINARY &  
PLENIPOTENTIARY OF THE  
REPUBLIC OF INDIA TO MONGOLIA

**ON BEHALF OF THE GOVERNMENT  
OF MONGOLIA**

Sd/-  
( D. DORLIGJAV )  
MINISTER FOR JUSTICE OF  
MONGOLIA

[ F. No. V-17011/04/2015-PR ]  
DILIP KUMAR, Jt. Secy.